UNIVERSITY NEWS 29 OCTOBER 2026

HINDUSTAN

एलयू में विषम सेमेस्टर की परीक्षा अब 17 नवंबर से

कार्यक्रम



लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। छठ पूजा और अन्य आपत्तियों को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने संशोधित अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत बीए एनईपी, बीकॉम रेगुलर और बीएससी एनईपी की परीक्षाओं की तिथियां बदली गई हैं। पहले जारी प्रस्तावित कार्यक्रम में परीक्षाएं 12 और 13 नवंबर से शुरू होनी थीं, लेकिन संशोधित कार्यक्रम में इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है।

बीए एनईपी की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं पहले 12 नवंबर से प्रस्तावित थीं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू होंगी और 19 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षा तिथियों में बदलाव के बाद विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और परीक्षा संबंधी कार्यक्रम उसी के अनुसार तय करना होगा। वहीं, बीकॉम एनईपी न्यू के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं भी निर्धारित तिथि से आगे बढ़ाई गई हैं। पहले ये परीक्षाएं 13 नवंबर से शुरू होनी थीं, लेकिन अब 18 नवंबर से शुरू होंगी। इनका आयोजन 27 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं बीकॉम ओल्ड एनईपी की परीक्षा 18 नवम्बर से 30 नवम्बर तक होंगी। दोनों सेमेस्टर के विद्यार्थियों को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा। इसी तरह बीएससी एनईपी रेगुलर की परीक्षाओं में भी बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षाएं 13 नवंबर से प्रस्तावित थीं, लेकिन अब 19 नवंबर से शुरू होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होंगी। बीएससी इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं भी इन्हीं तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद विद्यार्थियों को सलाह है कि वे अपनी परीक्षाओं की विषयवार तिथियां संशोधित कार्यक्रम में देख लें। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विषम सेमेस्टर की परीक्षा सुबह और दोपहर की पालियों में होगी।

पॉलीटेक्निक: विषम सेमेस्टर परीक्षा 16 से

प्रदेश के सभी पॉलीटेक्निक संस्थानों में विषम सेमेस्टर, विशेष बैक पेपर नवम्बर-दिसम्बर परीक्षा का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर कर दिया गया है। परीक्षा 16 नवम्बर से शुरू होंगी और 30 नवम्बर तक होंगी।

AMAR UJLA

एआई के जरिये पुस्तकालयों को हाईटेक करने की तैयारी

लविवि में 14वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर शिखर सम्मेलन कल से

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ शुक्रवार से लखनऊ विश्वविद्यालय में जुटेंगे। एक नवंबर तक चलने वाले 14वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर शिखर सम्मेलन (आई-लिप्स 2026) में देश-विदेश के पुस्तकालय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता और सूचना विज्ञान के पेशेवर जुटेंगे। लखनऊ में यह आयोजन दूसरी बार हो रहा है।

आयोजन सचिव और लविवि में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रविश प्रकाश ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य पुस्तकालयों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, ज्ञान के संरक्षण और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक उपाय तलाशना है। आयोजन लविवि के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग तथा टैगोर पुस्तकालय की ओर से किया जा रहा है।

उद्घाटन शुक्रवार को मालवीय सभागार में होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में फ्रांस, श्रीलंका, नॉर्वे, सिंगापुर और थाईलैंड समेत विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। पहले दो दिनों में पांच सत्रों में करीब 100 शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सत्र टैगोर पुस्तकालय सभागार और सामाजिक कार्य विभाग के सभागारों में होंगे। एक नवंबर को प्रतिभागियों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।



तीन दिवसीय सम्मेलन में कई देशों के पेशेवर लेंगे हिस्सा

शहर के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासतों का भ्रमण करेंगे प्रतिभागी

■ **डिजिटल पुस्तकालयों में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा :** सम्मेलन में एआई के जरिये डिजिटल पुस्तकालयों को अधिक उपयोगी बनाने और अकादमिक लेखन में जनरेटिव एआई के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। उच्च शिक्षा में एआई के प्रभावी उपयोग के साथ एआई की मदद से होने वाले शोध की विश्वसनीयता और जोखिमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में पुस्तकालयों की भूमिका, शोध को बढ़ावा देने पर भी मंथन होगा। सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी।

स्तन में असामान्य बदलाव पर कराएं जांच

लखनऊ। लविवि के विधि संकाय के प्रो. बोनो क्लब की ओर से बुधवार को स्तन कैंसर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें केजीएमयू के विशेषज्ञों ने छात्राओं को स्तन कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय बताए। केजीएमयू के डॉ. कुलरंजन सिंह ने स्तन कैंसर की प्रकृति और इसके शुरुआती लक्षणों की जानकारी दी। डॉ. पूजा रमाकांत ने इसके प्रमुख कारणों पर चर्चा की।

अंतःस्रावी शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष प्रो. आनंद कुमार मिश्रा ने बचाव के उपाय बताए। उन्होंने छात्राओं को स्तनों की स्वयं जांच के महत्व से अवगत कराया। साथ ही शरीर में किसी भी असामान्य बदलाव पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही। इस दौरान संकाय प्रभारी प्रो. आलोक यादव, अतिरिक्त प्रॉक्टर प्रो. अभिषेक तिवारी और विशेष यादव आदि मौजूद रहे। (माई सिटी रिपोर्टर)

चीन की शक्ति से भारत की परमाणु नीति पर बढ़ रहा दबाव



लखनऊ। चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति से भारत की परमाणु रणनीति पर दबाव बढ़ रहा है। यह निष्कर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के पाश्चात्य इतिहास विभाग के सहायक आचार्य आशुतोष सिंह के शोध में सामने आया। उनका शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'जर्नल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स : वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' में प्रकाशित हुआ। शोध में समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में हो रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला गया। भारत की पहले परमाणु हमला नहीं और विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की नीति कायम है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी पनडुब्बियां तथा के-15 और के-4 मिसाइलें विकसित की जा रही हैं। यह समुद्र से जवाबी परमाणु हमला करने की भारत की क्षमता मजबूत कर रहा है। अध्ययन बताता है कि मूल नीति में बदलाव के बजाय परिचालन रणनीति में क्रमिक अनुकूलन हो रहा है। (माई सिटी रिपोर्टर)

नया नगर बसाने जैसा था कुंभ मेले का प्रबंधन: डॉ. अनूप चंद्र पांडेय



लखनऊ। लविवि के लोक प्रशासन विभाग में बुधवार को पूर्व मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने कुंभ मेले के प्रबंधन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने परियोजना प्रबंधन में सहयोग और समन्वय के महत्व के बारे में बताया। डॉ. पांडेय ने कहा कि कुंभ मेले का आयोजन एक नया नगर बसाने जैसा है। इतने बड़े आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल, योजनाबद्ध कार्य और प्रभावी प्रबंधन जरूरी है। विभागाध्यक्ष प्रो. वैशाली सक्सेना ने डॉ. पांडेय के प्रशासनिक अनुभवों को विभाग के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक बताया। संचालन श्रेया यादव ने किया। इस दौरान डॉ. सुशील सिंह चौहान, डॉ. नंदिता कौशल, डॉ. सुशील सिंह चौहान सहित विभाग के शोधार्थी और विभिन्न विभागों के विद्यार्थी शामिल रहे। (माई सिटी रिपोर्टर)

HINDUSTAN

शोध: परमाणु नीति में बदलाव के संकेत नहीं

लखनऊ। भारत की परमाणु नीति में फिलहाल किसी बड़े बदलाव के स्पष्ट संकेत नहीं हैं लेकिन चीन की बढ़ती सामरिक ताकत और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता विकसित करने की जरूरत ने भारत की रणनीति पर दबाव बढ़ा दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पाश्चात्य इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आशुतोष सिंह के शोध में यह बात सामने आई है। उनका शोध पत्र जर्नल जर्नल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ में प्रकाशित हुआ है। डा. आशुतोष सिंह ने बताया कि शोध में सुरक्षा हालात का विश्लेषण किया गया है।

AMRIT VICHAR

लुआक्टा ने नियमों के पालन करने की रखी मांग

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के संगठन (लुआक्टा) ने प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर अपनी मांगे रखी है। संगठन ने सीएएस प्रोन्नति की समयबद्ध व्यवस्था का निदेशालय स्तर पर पालन न होने को लेकर नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा है कि राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) प्रोन्नति समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जानी है। इस आदेश का उद्देश्य प्रोन्नति को शीघ्र, पारदर्शी और समय सीमा में क्रियान्वित करना था।

तंबूओं के शहर महाकुंभ पर हुई परिचर्चा

लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में किस्सा प्रशासन का द्वितीय अध्याय कुंभमेला का आयोजन रहा। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पांडेय ने कुंभ के प्रबंधन की चर्चा की तथा परियोजना प्रबंधन में सहयोग और समन्वय के महत्व को समझाया। अनूप चंद्र ने कुंभ मेले के प्रबंधन की तुलना एक नए नगर बसाने के समान बताया। डॉ. सुशील सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया।

NBT

छठ के बाद शुरू होंगी LU की परीक्षाएं

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** लखनऊ विश्वविद्यालय में अब छठ पूजा के बाद से सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। विवि की ओर से हाल में परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया गया था। इसमें 12 नवंबर से विवि में सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित थीं लेकिन 15 नवंबर को छठ पूजा है। ऐसे में बहुत से छात्र दूसरे जिलों से विवि में पढ़ रहे हैं जो छठ के मौके पर घर जाते हैं। ऐसे में छात्रों की ओर से मांग की गई थी कि विवि परीक्षाएं उसके बाद कराई जाए। विवि ने अब परीक्षाओं को री-शेड्यूल कर दिया गया है। नए शेड्यूल के तहत अब 17 नवंबर से एलयू में परीक्षाओं की शुरुआत की जाएगी।

30 तक भर सकते हैं फॉर्म : विवि की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म जारी किया गया था जिसकी अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऐसे में विवि की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। इसके तहत छात्र 30 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

मुख्यमंत्री एलयू में करेंगे Gen-Z से संवाद



सीएम योगी आदित्यनाथ अब चुनाव से पहले Gen-Z से मुखातिब होंगे। वह न सिर्फ युवाओं के सामने अपने बात रखेंगे बल्कि Gen-Z के सवालों का जवाब भी देंगे। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। नवंबर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेशभर से एलयू के डिग्री कॉलेजों के डेढ़ हजार से अधिक छात्र शामिल होंगे। इसके लिए तैयारी की जा रही है। विवि की रजिस्ट्रार भावना मिश्रा ने बताया कि विवि की ओर से तैयारी कर ली गई है। आर्ट फैकल्टी ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया जाएगा।

अब कोर्ट से तय होगी कर्मचारियों की राजनीति

एलयू में कर्मचारी परिषद के अस्तित्व को लेकर चल रहा विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संगठन के बीच इस मामले में एक सुनवाई हो चुकी है, जबकि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

विवि प्रशासन ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर कर्मचारी परिषद को भंग घोषित कर दिया था। एलयू में पिछले तीन साल से परिषद के चुनाव नहीं हुए थे। कर्मचारियों का एक धड़ा चुनाव कराने की मांग कर रहा था। प्रशासन के आदेश को कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कर्मचारी नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन प्रशासन ने दोबारा पत्र जारी कर कहा कि कर्मचारी परिषद अस्तित्व में नहीं है। कर्मचारी परिषद के राफेश यादव का कहना है कि अप्रैल में परिषद भंग करने का आदेश वापस ले लिया गया था। ऐसे में परिषद किस आधार पर अस्तित्व में नहीं है, विवि को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं, विवि प्रशासन आदेश वापस लेने की बात से इनकार कर रहा है। रजिस्ट्रार भावना मिश्रा ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विवि कोर्ट में पक्ष रख रहा है। जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।

TIMES OF INDIA

LU starts biometric verification

Lucknow: Lucknow University has started biometric verification of scholarship applicants from Wednesday to minimise errors in the verification process and to ensure that applications are linked to the correct student records.

According to an office memorandum issued by the university's Dean of Students' Welfare (DSW), biometric authentication is being used to establish the identity of students applying for scholarships.

The move is aimed at improving the accuracy of the verification process and reducing the possibility of duplicate entries, incorrect identification and discrepancies in student records.

Lucknow University spokesperson Mukul Srivastava said, "Biometric verification will help establish the identity of scholarship applicants and ensure greater accuracy in the verification process". TNN

DAINIK JAGRAN

पालिसी रिसर्च के लिए लवि ने गठित की कमेटी

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेंटर फार डेवलपमेंट एंड पालिसी रिसर्च के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें जियोलाजी विभाग के प्रो. ध्रुव सेन सिंह, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के प्रो. अजय प्रकाश, अर्थशास्त्र विभाग की प्रो. रोली मिश्रा, डा. हरनाम सिंह, अप्लाइड इकोनामिक्स से डा. नागेंद्र मौर्य, सांख्यिकी से डा. अशोक कुमार शामिल हैं। वि.

भारत की परमाणु नीति में बदलाव के नहीं मिले पर्याप्त साक्ष्य

लखनऊ : लवि के पाश्चात्य इतिहास विभाग के सहायक आचार्य डा. आशुतोष सिंह का शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जर्नल जर्नल आफ वर्ल्ड अफेयर्स- वायस आफ द ग्लोबल साउथ में प्रकाशित हुआ है। शोध में भारत की परमाणु नीति, समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। इंडियाज न्यूक्लियर पोस्चर अंडर स्ट्रेस : द फ्यूचर आफ रिसेस्ड डिटरेंस शीर्षक वाले उनके शोध पत्र के अनुसार, भारत की परमाणु नीति के सिद्धांतों में औपचारिक बदलाव के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इनमें पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति और विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता शामिल हैं। हालांकि, चीन की बढ़ती सामरिक क्षमताओं और तकनीकी विकास के कारण भारत की परमाणु तैयारियों पर दबाव बढ़ रहा है। वि.

AMRIT VICHAR

चीन के कारण भारत की परमाणु नीति में आ रहे बदलाव

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: भारत ने परमाणु परीक्षण के बाद ही नो फर्स्ट यूज भारत की परमाणु नीति घोषित की थी, लेकिन चीन की बढ़ती सामरिक क्षमता और दिनोंदिन तकनीकी में आ रहे अपग्रेडेशन के बाद भारत के परिचालनगत परमाणु मुद्रा में क्रमिक अनुकूलन हो रहा है। यह बातें लखनऊ विश्वविद्यालय के एक शोध में सामने आई हैं। अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध में भारत की परमाणु नीति और 'रिसेस्ड डिटरेंस' पर विश्लेषण किया गया है। विश्वविद्यालय के डॉ. आशुतोष सिंह ने सिपरी रिपोर्ट 2026 और समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में भारत की 'नो फर्स्ट-यूज' और 'क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस' का विश्लेषण किया है।



डॉ. आशुतोष सिंह।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की 2026 की रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत ने अपनी किसी एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर लगभग 12 परमाणु वारहेड तैनात किए हो सकते हैं। इस आकलन ने भारत की पारंपरिक 'रिसेस्ड डिटरेंस' व्यवस्था की प्रासंगिकता पर बहस शुरु कर दिया है। इस व्यवस्था में शांतिकाल के दौरान परमाणु वारहेड और उनकी प्रक्षेपण प्रणालियों को अलग रखा जाता है और परमाणु बलों को अपेक्षाकृत कम परिचालन तत्परता पर बनाए रखा जाता है। डॉ. सिंह के शोध के अनुसार विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमले की क्षमता बनाए रखने की आवश्यकताओं और चीन की बढ़ती सामरिक क्षमताओं के कारण भारत की पारंपरिक परिचालनगत परमाणु मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है।

मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं

■ भारत की परमाणु नीति अब भी नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस' जवाबी कार्रवाई पर आधारित है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों व के-15 और के-4 पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास भारत की समुद्र आधारित जवाबी परमाणु क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

चीन की सामरिक क्षमताओं का प्रभाव

■ चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स व उन्नत सटीक प्रहार तकनीकों ने भारत की परमाणु प्रतिरोधक रणनीति के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं। अध्ययन में भारत की परमाणु मुद्रा में क्रमिक अनुकूलन और 'रिसेस्ड डिटरेंस' के आंशिक क्षरण के संकेत मिलते हैं।

शोध का राष्ट्रीय महत्व

■ यह शोध रेखांकित करता है कि भारत की परमाणु नीति और उसकी परिचालनगत परमाणु मुद्रा का आकलन अलग-अलग किया जाना चाहिए। भारत की मूल परमाणु नीति में औपचारिक परिवर्तन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जबकि समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकताओं, चीन की बढ़ती सामरिक क्षमताओं और तकनीकी विकास के कारण उसकी परिचालनगत परमाणु मुद्रा में क्रमिक अनुकूलन हो रहा है।